(b) and (c) As reported by the All India financial institutions, 12 applications were received by them during the last 2 years for financial assistance for setting up mini steel projects. Of these, financial assistance has been sanctioned to 9 projects, while two proposals have been treated as closed due to various reasons such as inability of the promoters to raise the required funds, market prospects, uneconomic size, etc. In respect of the remaining proposal, necessary information has not been furnished by the applicant.

Losses suffered by Visakhapatnam Steel Plant

2232. DR. NARREDDY THULASI REDDY: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Visakhapatnam Steel Plant is running in huge losses;

(b) if so, what are the losses for the last three years, year-wise;

(c) what are the reasons for the losses; and

(d) what steps are being taken to make it profitable?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) The financial year 1990-91 was the first year of the operation of the Visakhapatnam Steel Plant. Following are the losses suffered by the Steel Plant during 1990-91 and 1991-92 :—

Year	Net loss
	(Rs. in crores)
1990-91	477.55
1991-92	986.93

(c) The losses were mainly due to the fact that the production units commissioned during the last two years are in the process of stabilisation which resulted in low capacity utilisation coupled with high incidence of capital related charges viz. depreciation and interest.

(d) Government is considering various options to restructure the capital base of the company so as to ensure its long term viability.

लोहे पर नियंत्रण हटाया जाना

2233. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहे पर सभी प्रकार के प्रतिबंध हटा लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ता बाजार पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

इस्पात मंत्रालय राज्य के मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : : (क) "लोहा और इस्पात उद्योग" को सरकारी क्षेत्र के लिये आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है तथा स्थान स्थिति संबंधी कुछ प्रतिबंधों को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है। लोह और इस्पात के मूल्य निर्धारण तथा वितरण का नियंत्रण भी समाप्त कर दिया गया है तथापि, रक्षा, रेलवे इंजीनियरी माल के निर्यातकों, लघु उद्योग क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को सप्लाई के लिये वितरण में प्राथमिकता दी जाती रहेगी। लोहे और इस्पात की सभी मदों के आयात करने की भी अनुमति है ।

(ख) आशा है कि इन उपायों से निजी क्षेत्र में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता सृजित करने में प्रोत्साहन मिलेगा और लोहा तथा इस्पात उद्योग अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होगा और इससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा ।